जल संसाधन विभाग

बजट घोषणा वर्ष 2016-17

क.सं.	घोषणा	कियान्विति रिपोर्ट
1	**बिन्दु संख्या 405.0.0** कुशलगढ तहसील में 9 करोड 7 लाख रूपये की लागत से 2 Micro Storage Tanks का निर्माण।	कुशलगढ तहसील के 2 Micro Storage Tanks की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 03.11.2016 को राशि क्रमशः रू. 4.23 करोड (ग्राम–खजुरा) एवं रू. 4.97 करोड (ग्राम–वाडला की रेल) की जारी की जा चुकी है। निविदा स्वीकृत कर कार्यदेश दिनांक 10.03.2017 को जारी किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की दिनांक 20.09.2017 प्रस्तावित है। **Task Started But Not Completed**
2	**बिन्दु संख्या 31.0.0** सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर 213 करोड रुपये की लागत आयेगी	बत्तीसा नाला परियोजना ग्राम –देलदर, तहसील–आबूरोड के समीप बत्तीसा नाला पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित हैं। परियोजना की **प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति** राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28. 07.2016 को **राशि रू. 228.05 करोड** की जारी की गई हैं। जिसमें पेयजल हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षित पानी का समानुपातिक हिस्सा राशि रूपये 108.20 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन किए जाने की सहमति प्रदान की गई हैं। प्रस्तावित परियोजना में बांध की कुल भराव क्षमता 577.40 Mcft तथा उपयोगी भराव क्षमता 500. 40 Mcft हैं। बांध में उपलब्ध पानी में से 269.80 Mcft जल का उपयोग सिरोही जिलें कें 31 गांवो व 2 शहरों को पेयजल सुविधा हेतु तथा शेष 230.60 Mcft पानी से ग्राम देलदर, शरजा इत्यादि गांवों की 900 हैक्टर क्षैत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं। **प्रगति–प्रतिवेदन** **1. वन भूमि के अवानिकरण की कार्यवाही :–** परियोजना से प्रभावित वन भूमि के अवानीकीकरण की अनापत्ति हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेब पोर्टल पर दिनांक 24.11.2016 को ऑनलाईन करते हुए उक्त प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये, जिन पर वन सलाहकार समिति की बैठक 28.02. 2017 को आर.एण्ड आर. प्लान की प्रति प्रस्तुत करने एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत भूमि का विवरण मांगा गया है, जो कि आगामी प्रस्तावित बैठक में

क्र.सं.	घोषणा	कियान्विति रिपोर्ट
		प्रस्तुत किया जाना है। **2. <u>निजी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही :–</u>** परियोजना से प्रभावित निजी भूमि को अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है। पुनर्वास व पुनर्व्यस्थापन हेतु प्रषासक की नियुक्ति की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.12.2016 को जारी की जा चुकी हैं। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा 08.02.2017 को किया गया है। डूब क्षैत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों व परिसम्पतियों का फील्ड सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्लान तैयार किया गया है। विस्थापितों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भूमि चिन्हित की गई है, जिस पर प्रभावित परिवारो की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रशासन व विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे है। तत्पश्चात पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन प्लान को अनुमोदन हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किया जायेगा तथा भूमि अवाप्ति की धारा–19 व पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्लान अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रभावित परिवारों द्वारा विरोध व पुनर्वास सहमति नही होने से इसमें देरी हो रही हैं। **3. भू–<u>गर्भीय सर्वेक्षण :–</u>** परियोजना में बांध निर्माण स्थल की Foundation Exploration के लिये भू–गर्भीय सर्वेक्षण हेतु जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (GSI) के साथ अनुबन्ध सम्पादन किया गया है। **Task Sanctioned But Not Started**
<u>3</u>	**<u>बिन्दु संख्या 101.01.0</u>** गंगनहर के आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।	दिनांक 27.3.17 से 20.4.2017 तक की बंदी में निर्माणाधीन 5 क्रोस रेगुलेटरों का निर्माण पूर्ण कर गंगनहर फीडर से लिंक किया जा चुका है एवं गंगनहर फीडर के शेष कच्चे भाग 0.98 किमी. को पक्का किया जा चुका है और वितरिका एवं माईनरों का शेष रहा 5.20 किमी. कार्य पूर्ण हो चुका है। वितरिका/माईनरों में पुलों /ग्रेवाल सडक इत्यादि का कार्य दिनांक 30.9.2017 तक पूर्ण किया जाना है।

क्र.सं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
		Task Started But Not Completed
4	**बिन्दु संख्या 101.02.0** बारां जिले में प्रगतिरत ल्हासी परियोजना का कार्य जून 2016 में पूर्ण कर आगामी वर्ष में जल भराव किया जायेगा।	परियोजना में बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मानसून, 2016 में जल भराव प्रारम्भ कर दिया गया है। **Implemented**
5	**बिन्दु संख्या 101.03.0** पिडावा तहसील झालावाड में निर्माणाधीन गागरीन सिंचाई परियोजना के बाँध का कार्य पूर्ण कर इसमें भी जल भराव जून 2016 से प्रारंभ कर दिया जायेगा।	गागरीन सिंचाई परियोजना के बाँध का कार्य पूर्ण हो चुका है, मानसून, 2016 में जल भराव प्रारम्भ कर दिया गया है। **– Implemented**
6	**बिन्दु संख्या 101.05.0** सिंचाई क्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढीकरण के लिए आगामी वर्ष में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर एवं CAD विभाग के लिए वर्ष 2016–17 में 4 हजार 47 करोड 44 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। जो वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान से 27.81 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, आगामी वर्षों में हम निम्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रारंभ करेंगे: :–	विवरण निम्नानुसार है :–
7	**बिन्दु संख्या 101.06.0** राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के rehabilitation के कार्यों, water user associations की क्षमतावर्धन एवं सिंचित कृषि विविधता हेतु आगामी 8 वर्षों के लिए Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project चलाया जायेगा। इस योजना के तहत 24 जिलों की 63 मध्यम एवं 370 लघु परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जायेगा तथा 4 लाख 66 हजार हेक्टेयर से भी अधिक सिंचित क्षेत्र को इससे लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3 हजार 461 करोड रुपये का व्यय होगा।	परियोजना के अन्तर्गत 25 जिलों से चयनित नहरों एवं बांधो का जीर्णोद्वार करवाया जावेगा। परियोजना की अनुमानित लागत राशि रू0 2606.2 करोड हैं तथा परियोजना से 4.68 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में कृषकों का लाभ मिलेगा। परियोजना जापान इन्टरनेशनल कोर्पोरेशन एजेन्सी (JICA) के सहयोग से किया जावेगा। जायका से ऋण अनुबंध कर लिया गया है। परियोजना का कार्यकाल आठ वर्ष हैं। परियोजना को तीन चरणों में पूर्ण किया जावेगा। प्रथम चरण में 16 जिलों की 34 सिंचाई उपपरियोजनाओं का चयन किया गया हैं जिसमें बांध एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य कराया जावेगा, जिससे 1.84 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में कृषको को लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु बजट अनुमान 18.00 करोड रू. रखा गया है।

क्र.सं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
		Task Sanctioned But Not Started
8	**बिन्दु संख्या 101.07.0** रबि, ब्यास, सतलज एवं घग्घर नदियों के बाढ के रूप में बहने वाले अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गाँधी नहर प्रणाली का restructuring कर Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area चलाया जायेगा। परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूप से इंदिरा गाँधी नहर फीडर का हरियाणा व राजस्थान में एवं इंदिरा गाँधी मुख्य नहर एवं शाखाओं की relining प्रस्तावित है। तीन हजार 264 करोड रुपये की इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बाडमेर जिले लाभान्वित होंगे तथा 1 लाख 81 हजार 618 हेक्टेयर CCA के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा।	(I) आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.डी. का प्रोजेक्ट तखमीना राशि 3264 करोड़ का केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहाकार समिति द्वारा Accept कर लिया गया है। इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है :–(I) इन्दिरा गांधी फीडर की बुर्जी सं0 496.000 से 555. 000 (हरियाणा भाग) बुर्जी सं0 555.000 से 671.000 (राजस्थान भाग) एवं इन्दिरा गांधी की मुख्य नहर की आर.डी. 0.000 से 200.000 तक की रिलाईनिंग की राशि 1157.58 करोड़ रूपये है। (II) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के बहाव क्षेत्र की वितरण प्रणाली की Extension, Renovation and Modernisation (ERM) के कार्य जिसके अन्तर्गत नहरों की मरम्मत, डिफेक्ट बैड की रिपेयरिंग एवं रिलाईनिंग आदि के कार्य सम्मिलित है। इन कार्यो की कुल लागत 969. 08 करोड़ है। (III) सेम समस्या के स्थाई समाधान हेतु करवाये जाने वाले कार्य पर 298.31 करोड़ रूपये की योजना बनाई गयी है। (IV) इन्द्रिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की रि–लाईनिंग के दौरान पीने हेतु पानी की व्यवस्था हेतु इन्दिरा गांधी फीडर की बुर्जी सं0 629.000 से घग्घर डाईवर्जन चैनल (GDC) में पानी छोड़कर घग्घर डिप्रेशन नं0 6 में संग्रहित करने के लिए इस डिप्रेशन की लाईनिंग एवं डिप्रेशन नं0 6 से लिंक चैनल बनाकर इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी सं0 165 पर पम्पिग कर पुनः इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में डाले जाने का कार्य घग्घर डिप्रेशन नं0 6 का उपयोग वर्षा ऋतु के दौरान हरिके से व्यर्थ पाकिस्तान जा रहे पानी को संग्रहित करके सदुपयोग किया जा सकेगा। इस कार्य की लागत 584.19 करोड़ अनुमानित है। आरडब्ल्यूएसआरपीडी मे सम्मलित उपरोक्त चारों कार्यो के लिए BRICS से लॉन लेने का प्रकरण प्रकियाधीन है । **Task Sanctioned But Not Started**

क्र.सं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
9	**बिन्दु संख्या 101.08.0** बारां, झालावाड एवं कोटा जिले के किसानों का वर्षों पुराना परवन सिंचाई योजना का सपना अब सच होगा। इस योजना से झालावाड, बारां एवं कोटा जिले के कुल 313 गाँवों की 1 लाख 31 हजार हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी तथा इन जिलों के 820 गाँव पेयजल से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4 हजार 824 करोड रुपये है। इस योजना की क्रियान्विति हेतु बहुराष्ट्रीय या बाह्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्त पोषण की व्यवस्था की जायेगी। परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में इस हेतु 700 करोड रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है	• MoEF से अंतिम स्वीकृति पत्रांक 8–10/2012–एफ–6 दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। • परियोजना के पूर्ण डूब क्षेत्र से प्रभावित 17 ग्रामों के अवार्ड राशि रूपये 702.50 करोड़ के पारित किये जा चुके हैं। इसके विरूद्ध राशि रूपये 253. 39 करोड़ भूमि अवाप्ति अधिकारी झालावाड़ को सितम्बर–2016 तक हस्तांतरित की जा चुकी है। भुगतान प्रक्रियारत है। • वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 699.965 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 में 1000 करोड रूपयें का प्रावधान स्वीकृत है। • परियोजना के आंशिक रूप से डूब में आ रहे 30 ग्रामों की धारा–11 एवं धारा–19 का गजट नोटिफिकेशन एवं प्रकाशन का कार्य किया जा चुका है। परवन मुख्य बांध एवं टनल निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 28.04.2017 को प्राप्त कर ली गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। **Task Sanctioned But Not Started**
10	**बिन्दु संख्या 101.10.0** माही बाँध के बेक वाटर क्षेत्र से बांसवाडा तहसील के लोगो को 850 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु Drip एवं फववारा पद्धति से अम्बापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रथम का कार्य आगामी 3 वर्षो में 60 करोड रुपये की लागत से करवाया जायेगा।	अम्बापुरा लिफट सिंचाई परियोजना की डीपीआर बनाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर, डीपीआर तैयार करने हेतु दिनांक 02.02.2017 को कार्यादेश जारी किये जाकर, सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डीपीआर दिनांक 15.05.2017 तक बनाकर प्रस्तुत कर दी जावेगी। **Task Started, But Not Complete**
11	**बिन्दु संख्या 101.11.0** भरतपुर जिले की डीग तहसील में डीग escape channel की चैन 72 से डीग कस्बे तक जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।	राशि रू. 1.54 करोड लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय दिनांक 09.03.2017 को जारी की जा चुकी है। निविदा आमंत्रित कर ली गई है, जो दिनांक 11. 05.2017 को खोली जानी प्रस्तावित है। **Task Sanctioned But Not Started**
12	**बिन्दु संख्या 101.12.0** झालावाड दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर,	झालावाड दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली, डूंगरपुर, राजसमन्द एवं चित्तौडगढ जिले में सभी 11

क्र.सं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
	जयपुर, करौली, डूंगरपुर, राजसमन्द एवं चित्तौडगढ जिले में 11 एनिकटों का निर्माण कार्य 25 करोड 74 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।	एनिकटों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 6 एनिकटों के कार्यो के कार्यादेश जारी कर, कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। शेष एनिकटों की निविदा कार्यवाही प्रक्रिया में है, जो कि दिनांक 31.05.2017 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। **Task Started, But Not Completed**
13	**बिन्दु संख्या 101.13.0** झालावाड जिले की चवंली सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य 9 करोड 45 लाख रुपये की लागत से कराया जायेगा।	झालावाड जिले की चवंली सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार के 5 कार्यो हेतु राशि रू. 9.45 करोड रुपये के कार्यादेश दिनांक 04.11.2016 को जारी किये जा चुके है । दायीं मुख्य नहर एवं रायपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, सुवांस डिस्ट्रीब्यूटरी के कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। कार्य प्रगति पर है। **Task Started, But Not Completed**
14	**बिन्दु संख्या 101.14.0** पार्वती, कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल का उपयोग कर बारां, कोटा, बूँदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा करौली एंव धौलपुर को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के लिए, मैं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।	चम्बल बेसिन की पार्वती नदी एवं काली सिंध नदी को जोडने एवं नहर द्वारा पानी को धौलपुर पहुंचाने की परियोजना 'Eastern Rajasthan Canal Project" की डीपीआर बनाने हेतु प्रशासनिक एवं तकनिकी स्वीकृति पत्र क्रमांक 1653–54 दिनांक 31 मार्च 2016 के द्वारा राशि रूपयें 22.07 करोड की जारी की गई है । वेपकोस को कार्यादेश दिनांक 05.04.2016 को जारी किये जा चुके है। योजना का Tentative alignment स्वीकृत कर लिया गया है। डीपीआर बनाने का कार्य प्रगतिरत है। वेपकोस. द्वारा प्रस्तुत फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है। ड्राफ्ट डीपीआर दिनांक 30.05.2017 से पूर्व प्राप्त होना प्रस्तावित है। **Task Started But Not Completed**
15	**बिन्दु संख्या 101.15.0** साबरमती बेसिन का अधिशेष जल जो कि राज्य के बाहर व्यर्थ बह जाता है, का उपयोग कर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जवाई बाँध में ले जाकर उस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी जायेगी।	जवाई बांध पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत साबरमती बेसिन में उपलब्ध सरप्लस जल को जवाई बांध में डाईवट करने हेतु विस्तृत सर्वे कर डीपीआर तैयार करने हेतु अधिषाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड़, सुमेरपुर के आदेष दिनांक 22.11.2016 द्वारा राषि रूपये 845.00 लाख का कार्यादेष वेपकोर्स लि. गुडगांव को दिया गया है। वेपकोस द्वारा हाईड्रोलोजी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। वेपकोस के प्रतिनिधियों ने समीक्षा बैठक दिनांक 10.04.2017 में इसे समीक्षा पष्चात् अन्तिम रूप देकर इस माह के अन्त तक

क्र.सं.	घोषणा	कियान्विति रिपोर्ट
		केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को प्रेषित करने का आष्वासन दिया है। एरियल सर्वे हेतु अनुमति के लिऐ इस कार्यालय के पत्रांक 2867 दिनांक 23.02.2017 द्वारा निदेषक, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को लिखा गया है। आगामी समीक्षा बैठक दिनांक 09.05.2017 को रखी गई है। डीपीआर प्रस्तुत करने की निर्धारित दिनांक 30.11. 2017 है। **Task Started But Not Completed**
16	बिन्दु संख्या 101.16.0 बांसवाडा जिले की तहसील कुशलगढ सज्जनगढ गांगड तलाई, बागीदोरा तथा बांसवाडा के 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नयी सिंचाई क्षमता का सृजन कराये जाने हेतु माही के सेडल डेम से सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवायी जायेगी।	माही के सैडल डेम से सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु आकलन करवाया जा रहा है, इससे 132 गांवों में 26000 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है। डीपीआर तैयार करने हेतु तखमीना तैयार कर डीपीआर बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। **Task Sanctioned But Not Started**
17	बिन्दु संख्या 102.0.0 राज्य में उपलब्ध जल संसाधन, वर्षा जल व नदियों के जल के आकडों को राज्य स्तर पर एकत्रित करने एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आकडों का आदान प्रदान करने व सभी नागरिकों को internet के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में hydrological सूचना तंत्र विकसित किया जायेगा। इस परियोजना की लागत 128 करोड आयेगी तथा इसे आगामी 8 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।	128 करोड रूपयों की प्रारम्भिक पीआईपी National Hydrology Project के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, परियोजना का MoU दिनांक 14/10/2016 को हस्ताक्षर किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा राशि रूपयें 95.75 करोड की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। योजना के bid document की एक प्रति MoWR / World Bank को जांच हेतु प्रस्तुत की गई है। 98 लाख की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है। **Task Sanctioned But Not Started**

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

बजट घोषणा वर्ष 2016-17

क्र.सं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
1	**बिन्दु संख्या–101 (CAD)** आगामी वर्ष में चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा के तहत सुल्तानपुरा सब ब्रांच सिस्टम अयाना ब्रांच नहर सिस्टम, लक्ष्मीपुरा, खातोली, चरी, ईश्वरनगर, अरनेठा, चितावा, कुलिंदा, बाल्कासा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं कापरेन नहर शाखा के रिवेम्पिंग के कार्य 213 करोड 53 लाख रू. की लागत से करवाये जायेगे।	इस बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु लक्ष्मीपुरा, खातोली, डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य सुल्तानपुर सब ब्रांच सिस्टम अयाना ब्रांच नहर सिस्टम, चरी, ईश्वरनगर, अरनेठा, चितावा, कुलिंदा, बाल्कासा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं कापरेन नहर की निविदायें दरें अधिक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। उक्त कार्य हेतु पुनः निविदायें दिनांक 27.'02.2017 को प्राप्त कर, कार्यादेश जारी कर दिये गये है **– Task Started But Not Completed**